

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 273 बेमेतरा, शनिवार 30 मई 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 5 रुपये डाक पंजीयन- दुर्गा/1743290201/2025-27

संक्षिप्त समाचार

चलती ट्रेन में मिले नोटों की गड़्डियों से भरा बैग देख उड़े होश

हैदराबाद। हैदराबाद में जीआरपी ने देवगिरी एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहे एक व्यक्ति को शक और छानबीन के आधार पर पकड़ा. पृष्ठताछ और तलाशी लेने के बाद तो सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के तो होश फाखा हो गए. अमरावती के रहने वाले 40 साल के उस शख्स के पास से 1.22 करोड़ रुपये कैश मिले. पुलिस ने संदेह के आधार पर यात्री के लगेज की तलाशी ली और उसके पास से 1.22 करोड़ रुपये की नकदी बरामद हुई। देवगिरी एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहे एक व्यक्ति के पास से 1,22,70,000 रुपये रेलवे सुरक्षा बल ने बरामद किए। यह नकदी मुंबई से ट्रेन के जरिए लाया जा रहा था. सिकंदराबाद रेलवे पुलिस और आरपीएफ की टीम बोलारम और मलकाजगिरि रेलवे स्टेशनों के बीच मंगलवार को चेकिंग कर रही थी. चेकिंग के दौरान टीम को एक 40 साल का व्यक्ति पर शक हुआ जो अपने साथ संदिग्ध हालत में बैग लेकर जाता दिखा.

चंद्रमा की सतह के नीचे बर्फ मिलने के संकेत

नई दिल्ली। भारत के चंद्र मिशन चंद्रयान-2 ने चांद को लेकर एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कामयाबी हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्रयान-2 ऑर्बिटर से मिले आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों को चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास बने कुछ बहुत गहरे गड्ढों (क्रैटरों) के नीचे पानी की बर्फ छिपी होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। इस बड़ी खोज से आने वाले समय में इंसानी चंद्र मिशनों को बहुत मदद मिल सकती है। यह महत्वपूर्ण रिसर्च अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीके वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च के लिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित उन खास गड्ढों को चुना जहां अरबों सालों से सूरज की रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुंची है। विज्ञान की भाषा में इन हिस्सों को परमानेंटली शैडोड रीजन यानी हमेशा अंधेरे में रहने वाले क्षेत्र कहा जाता है। इन गड्ढों में सूरज की रोशनी न पड़ने के कारण यहां का तापमान माइनस 248 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इतने भयंकर ठंडे तापमान की वजह से ही यहां सदियों से मौजूद बर्फ आज भी पूरी तरह सुरक्षित जमी हुई है

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा

मेदिनीपुर। जिले के पिंगला इलाके में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। बंगाल एमटीएन ने मंगलवार देर रात क्षीराई गांव से मुरसलीन और गौतम खांडा नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये लोग भारतीय सिम कार्ड के ओटीपी पाकिस्तान के आईएसआई अधिकारियों को बेच रहे थे, जिनका इस्तेमाल व्हाट्सएप अकाउंट खोलकर भारत में जासूसी नेटवर्क चलाने के लिए किया जा रहा था। आईएसआई सूत्रों के अनुसार, पिंगला के एक मोबाइल सिम विक्रेता के यहां फर्जी दस्तावेजों के जरिए बड़ी संख्या में सिम कार्ड निकाले जा रहे थे।

राज्यपाल ने स्वीकार किया सिद्धारमैया का इस्तीफा

मंत्रिपरिषद तत्काल प्रभाव से भंग! शपथ ग्रहण की तैयारी

कर्नाटक/ एजेंसी

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भी तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। इसी के साथ राज्य में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, सिद्धारमैया ने 28 मई 2026 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपा था। राज्य में मौजूद न होने के कारण राज्यपाल ने इसे 29 मई 2026 को स्वीकार कर लिया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धारमैया को लिखे पत्र में कहा, मैंने आपके द्वारा प्रस्तुत इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते रहें। कर्नाटक सरकार की मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को भेजे गए पत्र में राज्यपाल के विशेष सचिव आर. प्रभु शंकर ने कहा कि संबंधित अधिसूचना के तहत सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और उनकी मंत्रिपरिषद भंग कर दी गई है। राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि सिद्धारमैया तब तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहेंगे, जब तक नए मुख्यमंत्री के चयन और शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। सिद्धारमैया के इस्तीफा देने के बाद कर्नाटक में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक जल्द बुलाए जाने की संभावना है, जिसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच नेतृत्व को लेकर लंबे समय से चल रही खींचतान इस घटनाक्रम की एक प्रमुख वजह मानी जा रही



ईश्वर न वरदान देता है-न ही अभिशाप

डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया की तारीफ करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। शिवकुमार ने कहा-ईश्वर न तो वरदान देता है और न ही अभिशाप। वह केवल अवसर देता है। मायने यह रखता है कि हम उस अवसर में क्या हासिल करते हैं। हमारे सिद्धारमैया इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। मैसूर जिले के एक गांव में जन्मे और पले-बढ़े, मेरे प्रिय मित्र सिद्धारमैया- जो संघर्ष के रास्ते राजनीति में आए, और सामाजिक न्याय के अग्रदूत तथा गरीबों के हमदर्द के रूप में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर रहे, ने अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है।

है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी हाईकमान की सलाह पर सिद्धारमैया ने इस्तीफा सौंपा है। अब नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम फैसला दिल्ली में पार्टी नेतृत्व द्वारा लिए जाने की संभावना है। हालांकि, डीके शिवकुमार का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। इस बीच कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और जल्द ही मुख्यमंत्री बनने

लोगों के दिलों में बसे सिद्धारमैया- डीके

शिवकुमार ने कहा- कर्नाटक के राजनीतिक इतिहास में सबसे सफल, प्रभावशाली और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया लोगों के दिलों में बसे हैं, और भारतीय राजनीति के एक कद्दावर नेता हैं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में-जन-हितैषी परियोजनाओं से लेकर जन-कल्याणकारी कार्यों तक-उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका लगभग पचास वर्षों का विशाल राजनीतिक अनुभव, सामाजिक सरोकार और जन-हितैषी परियोजनाएं सदैव स्मरणीय रहेंगी।

वाले डी के शिवकुमार ने शुक्रवार को सिद्धारमैया को लेकर एक भावुक पोस्ट किया है। पोस्ट में उन्होंने सिद्धारमैया को ताकत का एक स्तंभ बताया है। शिवकुमार ने सिद्धारमैया के मैसूर के गांव से निकलकर मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने के सफ़र को जूनून और समाज के प्रति प्रतिबद्धता के सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक बताया।

आठ घंटे में पहुंचें वैष्णो देवी

दिल्ली और कटरा एक्सप्रेसवे को मोदी सरकार की मिली मंजूरी....

नई दिल्ली/ एजेंसी

दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह एक हाई-स्पीड कॉरिडोर होगा, जो दिल्ली को हरियाणा, पंजाब और जम्मू-कश्मीर से जोड़ेगा। इसका नाम 'दिल्ली-कटरा एनई-5 एक्सप्रेसवे'होगा। छह-लेन वाले इस कॉरिडोर की अनुमानित लागत 1,500 करोड़ रुपये है। इसे मार्च 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत इस परियोजना को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में शामिल करने की



अधिसूचना जारी कर दी है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से उत्तर भारत में सड़क संपर्क मजबूत होगा। इसके बनने से दिल्ली से सिर्फ आठ घंटे में वैष्णो देवी पहुंच सकेंगे। अभी फिलहाल 10 से 14 घंटे लगते हैं। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली में

रानी खेड़ा गांव के पास एनएच-344एम से शुरू होगा और जसौर खेरी गांव के पास कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। एक्सप्रेसवे बनने के बाद हरियाणा से जम्मू-कटरा की यात्रा में काफी समय कम होने की उम्मीद है। माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं और ट्रांसपोर्ट कारोबार को इसका सबसे ज्यादा फ़ायदा मिलने की संभावना है। इससे जम्मू कश्मीर में धार्मिक पर्यटन को विशेषकर श्रीमाता वैष्णो देवी भवन और उसके आस पास के क्षेत्रों में स्थित धर्मस्थलों व अन्य पर्यटन स्थलों के विकास, प्रचार-प्रचार को भी एक नयी गति मिलेगी।

मुंबई एयरपोर्ट पर 2 कुख्यात गैंगस्टर गिरफ्तार, विदेश भागने की थी तैयारी

मुंबई। पंजाब पुलिस को मुंबई पुलिस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में बहुत बड़ी सफलता मिली है। जॉइंट ऑपरेशन में 2 कुख्यात गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया, ये दोनों विदेश भागने की तैयारी में थे. पंजाब पुलिस को कई संगीन मामलों में बहुत समय से वांटेड ये दोनों खतरनाक गैंगस्टरों को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों लंबे समय से फरार चल रहे थे. हत्या, फिरोती और अन्य कई संगीन मामलों में लंबे समय से वांछित थे. पंजाब पुलिस, मुंबई पुलिस, सीआईएसएफ और इमिग्रेशन अधिकारियों ने जॉइन्ट ऑपरेशन में मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश भाग रहे रहे दो गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है.

जमीन पर बैठकर लंच किया

राहुल गांधी ने ऑटो ड्राइवरों के साथ बैठकर खाना खाया

नई दिल्ली/ एजेंसी

कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का अनोखा अंदाज देखने को मिला है। राहुल गांधी ने ऑटो ड्राइवरों के साथ खाना खाने का वीडियो सामने आया है। राहुल गांधी ने के टोडरमल पार्क पहुंचे। यहां उन्होंने ऑटो ड्राइवरों की ड्रेस पहनी। इसके बाद उन लोगों के साथ जमीन पर बैठकर साथ खाना खाया। इस दौरान उन्होंने महंगाई, रोजगार, ईंधन की बढ़ती कीमतों और आम लोगों के जीवन पर पड़ रहे प्रभावों को लेकर ऑटो ड्राइवरों से बात की। दरअसल दिल्ली के बंगाली मार्केट में बने



टोडरमल पार्क में ऑटो ड्राइवर्स बैठकर खाना खा रहे थे। इसी दौरान अचानक राहुल गांधी पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी को अपने पास देखकर ऑटोरिक्षा ड्राइवर्स काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद राहुल गांधी ऑटो ड्राइवर से उसका यूनिफॉर्म मांगते हैं और उसे

पहने लेते थे। इसके बाद लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ऑटो ड्राइवरों के साथ जमीन पर बैठकर साथ खाना खाने लगते हैं। इस दौरान वे ऑटो की सवारी करते भी नजर आए। खाना खाने के दौरान राहुल गांधी ने ऑटो चालकों से महंगाई, रोजगार, ईंधन की बढ़ती कीमतों और आम लोगों के जीवन पर पड़ रहे प्रभावों पर बात की और उनकी राय जानी। साथ ही उनकी समस्याओं को भी सुना। इस दौरान कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। राहुल गांधी से मिलने के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा कि उन्होंने हमसे बातचीत की।

बैक टू बैक घटनाओं से मचा हड़कंप

एयरपोर्ट पर 6 फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग.....

नई दिल्ली। दिल्ली में रात तेज हवाओं और खराब मौसम के कारण विजिबिलिटी काफी कम रही। इस कारण विमानों की लैंडिंग संभव नहीं हो पा रही थी और सुरक्षा के मद्देनजर 6 विमानों को वैकल्पिक एयरपोर्ट के तौर पर लखनऊ डायवर्ट करना पड़ा। इस अचानक हलचल के कारण लखनऊ एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलग्राउंड स्टाफ और मेडिकल टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया था। इसके साथ एक प्लेन को ईंधन कम होने के कारण लैंड करना पड़ा। दिल्ली से मुंबई जा रही इस फ्लाइट को ईंधन कम होने की



स्थिति में लखनऊ भेजा गया। यह विमान रात 8:44 बजे लखनऊ पहुंचा और रीस्पूलींग के बाद मुंबई के लिए रवाना हुआ। दरअसल, पायलट ने ट्रैफिक कंट्रोलर को ईंधन कम होने की जानकारी दी, जिसके बाद विमान को लखनऊ डायवर्ट करने को कहा गया।

पॉक्सो मामले में मिली राहत

अब जेल नहीं जाएंगे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद-सुको....

नई दिल्ली/ एजेंसी

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में नाबालिग यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े पॉक्सो मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अग्रिम जमानत देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है।



आशुतोष ब्रह्मचारी ने यह याचिका पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत के साथ दायर की थी, जिसमें उन्होंने नाबालिग छात्रों के यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस मामले में 25 मार्च 2026 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के

जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य की अग्रिम जमानत पर फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ दोनों को गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। इस फैसले पर शंकराचार्य के समर्थकों का कहना था कि यह सत्य की जीत है। इस फैसले के खिलाफ शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से भी शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

अब सिर्फ 112-देशभर में एक ही इमरजेंसी नंबर लागू किया जाए

नई दिल्ली। एजेंसी

अब 100, 101, 102, 108 और 1091 जैसे अलग-अलग इमरजेंसी नंबरों के झंझट से लोगों को राहत मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि पूरे देश में आपातकालीन सेवाओं के लिए सिर्फ एक हेल्पलाइन नंबर 112 को पूरी तरह लागू किया जाए। 'सेव लाइफ फंडेशन' की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे अगले तीन महीने के भीतर 112 नंबर को पूरी तरह ऑपरेशनल करें। कोर्ट ने कहा कि ट्रामा के समय तुरंत इलाज मिलना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क हादसे या किसी गंभीर आपात

स्थिति में घायल व्यक्ति सदमे और घबराहट में होता है। ऐसे समय में मदद मिलने में हर मिनट की देरी उसकी जान के लिए खतरा बन सकती है। अदालत ने साफ कहा तेजी ही जीवनरक्षक दवा है। कोर्ट ने यह भी माना कि कई लोग घायल की मदद करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस पृष्ठताछ, कोर्ट-कचहरी और कानूनी परेशानियों के डर से पीछे हट जाते हैं। इसलिए राज्यों को प्रभावी 'गुड समैरिशन' शिकायत निवारण व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया गया है, ताकि मदद करने वालों को परेशान न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकारी और निजी सभी एंबुलेंस को AIS-125 मानकों के अनुसार GPS और Vehicle Location Tracking Device (VLTD) से लैस किया



जाए। इन सभी को 112 हेल्पलाइन से रियल-टाइम में जोड़ा जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत लोकेशन ट्रैक कर मदद पहुंचाई जा सके। अदालत ने कहा कि ट्रामा देखभाल और समय पर इलाज, संविधान के अनुच्छेद 21

के तहत 'जीवन के अधिकार' का हिस्सा है। केंद्र सरकार को ट्रामा मामलों के लिए मेडिकल रेस्क्यू प्रोटोकॉल जारी करने और राज्यों को उसे लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

‘तारीख पर तारीख’ का दौर खत्म.. सुको ने सभी हाईकोर्ट को दिए निर्देश, तीन महीने के अंदर सुनाना होगा फैसला

अदालतों में सालों तक चलने वाले केस कई बार व्यक्ति की सब्र का इम्तेहान ले लेते हैं. कई बार फैसले आने तक तो अपीलकर्ता की मृत्यु तक हो जाती है. बॉलीवुड की सुपरहिट मूवी ‘दामिनी’ में इसी कारण सनी देओल का डायलॉग फेमस हुआ था ‘तारीख पर तारीख’. यह केवल डायलॉग नहीं था बल्कि देश की न्याय व्यवस्था का स्याह सच उजागर करने वाला वाक्य था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने दशकों से चली आ रही इस भेड़ चाल पर रोक लगाने का फैसला कर लिया है. देश की शीर्ष अदालत ने लंबित मामलों और फैसलों में होने वाली देरी पर चिंता जताते हुए सभी हाईकोर्ट के लिए अनिवार्य दिशा-निर्देश जारी किए हैं. शीर्ष अदालत ने आरक्षित फैसलों, जमानत आदेशों और उनके कारणों को सार्वजनिक करने के लिए स्पष्ट समयसीमा तय कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि किसी भी मामले में फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद उसे अधिकतम तीन महीने के भीतर सुनाया जाना चाहिए. वहीं जमानत से जुड़े मामलों में आदेश आदर्श रूप से अगले दिन जारी किया जाए और उसी दिन जेल प्रशासन तक पहुंचाया जाए. अदालत ने यह भी कहा कि जिन अंडरटायल कैदियों को जमानत मिल चुकी है, उनकी रिहाई उसी दिन या अधिकतम अगले दिन सुनिश्चित की जानी चाहिए. नए दिशानिर्देशों के अनुसार, अदालत पहले आदेश का प्रभावी हिस्साखुले कोर्ट में सुनाएगी और उसके विस्तृत कारण सात दिनों के भीतर वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे. साथ ही, जिस दिन फैसला सुरक्षित रखा गया हो, उसकी जानकारी भी संबंधित हाईकोर्ट की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं किया जाता है तो मामला किसी अन्य पीठ को सौंपा जा सकता है.

संपादकीय

तेल खरीद को लेकर अमेरिका ने भारत पर जिस तरह की शंते थोपी, रूस से तेल खरीदने पर शुल्क में बढ़ोतरी की ज़िद ठानी, उससे साफ था कि वह इस मसले पर अपनी मनमानी थोपना चाहता है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के लिए वार्ता पिछले कई महीने से टुकड़ों में चलती रही है, लेकिन अब तक यह अंतिम स्वरूप में नहीं पहुंच सकी है। इसी क्रम में अमेरिका के विदेश मंत्री माकों रूबियो ने अपने ताजा भारत दौरे में एक बार फिर कुछ नए संकेत दिए, जिसमें इस मसले पर

कदम आगे बढ़ाए जाने की रूपरेखा बनती दिख रही है।हालांकि व्यापार वार्ता में अपने-अपने हित के मद्देनजर दोनों पक्षों की ओर से दबाव बनाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन पिछले कुछ समय से अमेरिका ने एकतरफा तौर पर जिस तरह की कसौटियां तय करने की कोशिश की है, वह कई मायनों में भारत के लिए सहज स्वीकार्य नहीं रही है। यही वजह है कि अब तक इस समझौते का अंतिम स्वरूप सामने नहीं आ सका है।अब अमेरिका की ओर से रूबियो ने जिस तरह परस्पर हित सुनिश्चित

किए जाने की बात की है, उससे इसमें सकारात्मक प्रगति की उम्मीद जगी है। गौरतलब है कि भारत के विदेश मंत्री के साथ व्यापक वार्ता के बाद रूबियो ने कहा कि यह व्यापार समझौता दोनों देशों के लिए ‘लाभकारी’ और ‘टिकाऊ’ होगा। साथ ही यह अमेरिका और भारत के पारस्परिक हितों को आगे बढ़ाएगा।निश्चित तौर पर अमेरिका की ओर से दिए गए ये संकेत बीते कुछसमय से आर्थिक मसले पर जारी तनाव के माहौल में नरमी लाने का ज़रिया हो सकते हैं, लेकिन यह देखने की बात होगी कि

व्यापार समझौता अपने अंतिम रूप में ‘परस्पर और समान हित’ के सिद्धांत पर आधारित होता है या नहीं।यह छिपा नहीं है कि अमेरिका ने कुछ महीने पहले दूसरे देशों से आयात पर पच्चीस से लेकर पचास फीसद तक शुल्क लगा कर किस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की थी। उसके इस रुख की वजह से दुनिया भर में प्रकाशंतर से व्यापार युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हो गई थीं।खासतौर पर तेल खरीद को लेकर अमेरिका ने भारत पर जिस तरह की शंते थोपी, रूस से तेल खरीदने पर शुल्क

में बढ़ोतरी की ज़िद ठानी, उससे साफ था कि वह इस मसले पर अपनी मनमानी थोपना चाहता है। उसका यह रुख किसी भी तरह से ‘परस्पर और समान हित’ को सुनिश्चित किए जाने की मंशा के अनुकूल नहीं लगता।अभी भी अमेरिका यही संदेश दे रहा है कि भारत उससे जितना तेल खरीदना चाहता है, उतना देने के लिए वह तैयार है। सवाल है कि तेल के लिए अगर भारत की निर्भरता केवल अमेरिका पर बनती है, तो इसके नतीजे क्या होंगे? अमेरिका एक विकल्प जरूर हो सकता है, लेकिन

अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जरूरी है कि भारत अपने लिए अन्य देशों के वैसे व्यापक और विश्वसनीय स्रोतों का रास्ता भी खुला रखे, जो ज्यादा बेहतर और सस्ते हों।पश्चिम एशिया में जारी तनाव की स्थिति और होमुंज जलमार्ग से आपूर्ति भूखंडा बाधित होने की वजह से गहराते संकट से सभी वाकिफ हैं। इसी को आधार बना कर आज सरकार तेल और गैस की कीमतों में लगातार इजाफा कर रही है और आम लोगों पर बोझ बढ़ता जा रहा है।

इन चुनौतियों के बीच पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। उसे और विकसित किया जा सकता है। इस पर काम करने की जरूरत है। भारत कई संस्कृतियों का देश है। इतनी विविधता वाला राष्ट्र दुनिया में कहीं नहीं हैं। कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत की एक अनूठी लोक संस्कृति भी है। ग्रामीण समाज के हर क्षेत्र की अपनी विशेषता है। अपने-अपने लोकगीत हैं और अपनी लोक परंपराएं हैं। राजस्व बढ़ेगा, पूंजी कमाने का नया रास्ता निकलेगा अगर इनकी ओर देश और विदेश के पर्यटकों को आकर्षित किया जाए, तो हमारा राजस्व बढ़ेगा। विदेशी पूंजी कमाने का एक नया रास्ता निकलेगा।

पर्यटन में संभावनाओं की नई डगर, ‘फॉर्मस्टे’ की भूमिका हो सकती है महत्त्वपूर्ण

(सुरेश सेठ)

अगर हम लोक संस्कृति के वाहक बन कर पूरे देश के ग्रामीण परिवेश को पर्यटकों के लिए विशेष पर्यटन क्षेत्र बना दें, तो सोचिए, इससे राजस्व में कितनी वृद्धि हो जाएगी। हमारे देश में पर्यटन को विशेष महत्त्व दिया गया है। वैसे तो भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन कमाई पर्यटन क्षेत्र से होती है। इसको कई तरीके से वर्गीकृत कर देखा जा सकता है जैसे, चिकित्सा पर्यटन और धार्मिक पर्यटन। इस तरह के पर्यटन से विदेशी राजस्व भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कई देशों से पर्यटक और यात्री भारत आते हैं और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को समृद्ध करते हैं।रमणीक स्थलों के पर्यटन को भी कमाऊ माना गया है। पहाड़ों, नदी किनारे और समुद्र तट पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। इस पर्यटन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। कई स्थलों का पुनरुद्धार कर पर्यटकों को आकर्षित किया गया है। आकर्षक पर्यटन स्थलों को देखने जब विदेश वे आते हैं, इससे देश को फायदा ही होता है।

मगर अब एक नया संकट हमारे सामने हैं। ईरान और अमेरिका युद्ध के कारण कच्चे तेल, गैस और ड्रवैक का भारी संकट पैदा हो गया है। देश के शीर्ष नेतृत्व ने मितव्ययी होने का संदेश दिया है। सोना न खरीदने, पेट्रोल-डीजल बचाने और विदेशी यात्राएं कम करने की नसीहत दी गई है। लक्ष्य एक ही है कि विदेशी पूंजी बचाई जाए, ताकि विदेशी विनिमय में हम अपने बजट घाटे और चालू घाटे को संभाल सकें और डालर के मुकाबले रूपए के गिरते जाने से बचा सकें।

इन चुनौतियों के बीच पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। उसे और विकसित किया जा सकता है। इस पर काम करने की जरूरत है। भारत कई संस्कृतियों का देश है। इतनी विविधता वाला राष्ट्र दुनिया में कहीं नहीं है। कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत की एक अनूठी लोक संस्कृति भी है। ग्रामीण समाज के हर क्षेत्र की अपनी विशेषता है। अपने-अपने लोकगीत हैं और अपनी-अपनी लोक परंपराएं हैं।

राजस्व बढ़ेगा, पूंजी कमाने का नया रास्ता निकलेगा

अगर इनकी ओर देश और विदेश के पर्यटकों को आकर्षित किया जाए, तो हमारा राजस्व बढ़ेगा। विदेशी पूंजी कमाने का एक नया रास्ता निकलेगा। हमारे सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े बताते हैं कि कृषि क्षेत्र के मुकाबले सेवा क्षेत्र से कहीं अधिक राजस्व प्राप्त होता है। सेवा क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र मुख्य भागीदार है।

अगर पर्यटन क्षेत्र में हम लोक संस्कृति से परिचय का एक नया आयाम जोड़ दें, तो पर्यटकों की एक बड़ी संख्या हमारे सामने होगी। देश के कई कोने पर्यटन का आकर्षण बन जाएंगे। भारत में विदेशी पर्यटकों की आमद इस तरह भी बढ़ाई जा सकती है। हमारी घरेलू दस्तकारियां, हमारे अनूठे लोक नृत्य और ग्रामीण समाज का लोक व्यवहार पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। बस इसको और प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इससे हम विदेशी पर्यटकों के लिए भारत में एक नई दुनिया खोज सकते हैं।

पिछले दिनों पंजाब में एक नई नीति शुरू हुई है जिसे ‘होमस्टे नीति’ कहा जाता है। इसमें पंजाबी संस्कृति की वैश्विक पहचान दिलाने का ‘मास्टर प्लान’ बनाया गया है। ‘होमस्टे’ को लेकर नवाचार या उससे जुड़े नव उद्यमियों के लिए आनलाइन पंजीकरण की नीति बनाई गई है। यह भी घोषणा की गई है कि ऐसे उद्यमियों को योजनाबद्ध तरीके से पांच करोड़ तक की सबसिडी दी जा सकती है।

मगर पंजाब ही क्यों, हम इसका विस्तार देश के हर राज्य में कर सकते

हैं, क्योंकि हर राज्य की ग्रामीण संस्कृति और उसका लोकाचार और व्यंजन अलग-अलग हैं। इसे बढ़ावा दें, तो पर्यटक देश के हर कोने में जाना पसंद करेंगे। इस प्रकार हम देखते ही देखते पूरे देश को पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थल बना सकते हैं। पंजाब में जो योजना बनाई गई है, इसका नाम ‘फार्मस्टे पालिसी 2026’ दिया गया है।

आजकल होटलों के अतिरिक्त रमणीक स्थलों पर आने वाले नव दंपतियों या विदेशी पर्यटकों को ‘होमस्टे’ की सुविधा दी गई है। हिमाचल और उत्तराखंड की सरकारें इस तरह के निवेश को अपने यहां प्रोत्साहित



कर रही है। अब पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों को पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाया जा सकता है। पंजाब ने इस दिशा में पहल कर दी है। अब यहां किसान पर्यटकों को ठहराने, खाने-पीने और ठेठ ग्रामीण जीवनशैली का अनुभव कराने की सुविधा शुरू कर सकेंगे।

पूरे देश में छोटे किसानों की की बड़ी संख्या

ध्यान देने की बात है कि पंजाब ही नहीं पूरे देश में छोटे किसानों की की बड़ी संख्या है, जिनके पास औसत क्षेत्र दो एकड़ से पांच एकड़ तक जमीन है। इससे आय इतनी कम होती है कि उनका जीना मुश्किल हो जाता है। आजादी के इतने साल गुजर जाने के बाद भी वे अपनी खेती को व्यावसायिक नहीं बना सके और आज भी उन्हें मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है।

मगर अब यह सहारा भी कमजोर पड़ने लगा है। पर्यावरण पर प्रदूषण की मार का असर उन पर भी पड़ा है। बारिश के मौसम में भीषण गर्मी पड़ती है और जब फसलें पकने लगती हैं तो बारिश होने लगती है। ऐसी स्थिति में किसानों को अतिरिक्त आय की जरूरत है। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को जो इस समय खेतीबाड़ी में हाथ बंटा कर परिवार का मदद करती है। उनको अतिरिक्त आय का साधन दिया जा सकता है।

वह साधन है- ‘फार्मस्टे’। इसमें इनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण हो सकती है। वे पर्यटकों को ठहराने और ग्रामीण जीवनशैली से परिचित कराने में सहयोग कर आय का उपार्जन कर सकती हैं।

अगर हम लोक संस्कृति के वाहक बन कर पूरे देश के ग्रामीण परिवेश को पर्यटकों के लिए विशेष पर्यटन क्षेत्र बना दें, तो सोचिए, इससे राजस्व में कितनी वृद्धि हो जाएगी। यही सोच कर पंजाब ने नई नीति बनाई है। पहाड़ों में बने ‘होमस्टे’ की तर्ज पर ‘फार्मस्टे’ को विकसित किया जा रहा है। ऐसा हर राज्य क्यों न करें? सभी राज्यों की अपनी लोक संस्कृति है और अपना ग्रामीण आकर्षण।

पंजाब आने वाले पर्यटक खेतों में रह कर ट्रैक्टर चलाने, बैलगाड़ी की सवारी करने, पशुपालन देखने और गांवों के पारंपरिक खानपान व रहन-



सहन को करीब से महसूस कर सकेंगे। इसी प्रकार हर राज्य अपनी-अपनी ग्रामीण संस्कृति के अन्वेषण और अपने लोकगीतों एवं लोकनृत्यों से पर्यटकों को लुभा सकता है।

पंजाब में यह तय किया गया कि इस तरह के पर्यटन के लिए किसान के पास कम से कम एक एकड़ कृषि भूमि जरूर हो। इस प्रकार यहां के छोटे किसानों को अतिरिक्त आय का एक साधन मिल गया है। पंजाब में बनी नई नीति में साफ किया गया है कि कुल जमीन के केवल दस फीसद हिस्से पर ही निर्माण किया जा सकेगा, जबकि बाकी 90 फीसद क्षेत्र खुला रहना होगा, ताकि पर्यटकों के लिए खेती और उसका प्राकृतिक स्वरूप बना रहे।

पंजाब में इस परियोजना पर निवेश में दस फीसद सबसिडी मिलेगी। इसकी अधिकतम सीमा पंच करोड़ है। विदेशी पर्यटक आते हैं तो ‘फार्मस्टे’ संचालक को 24 घंटे के भीतर फार्म-सी भ्रमकर प्रशासन को सूचना देनी होगी और ध्यान रखना होगा कि उनका ‘फार्मस्टे’ ग्रामीण परिवेश को बरकरार रखे। गांवों की शांति और सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। यह योजना अपने आप में महत्त्वपूर्ण है।

इससे पहले निर्यात के लिए भी हर राज्य की दस्तकारी को विशेष रूप से प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। मगर इन योजना में क्योंकि साधारण व्यक्ति का अपना उद्यम शामिल है, इसलिए इसके कामयाब होने की गुंजाइश काफी अधिक है।

स्पंदनों का संगीत, जीवन का कैनवास और भीतर के रंग

जीवन कोई समस्या नहीं, जिसे हल किया जाए, यह एक संगीत है, जिसे सुना जाए, जिया जाए और पूरी सजगता के साथ रचा जाए

(मनीषा मंजरी)

अक्सर हम जीवन को उन दृश्यों में बांध देते हैं, जो हमारी आंखों के सामने घटित होते हैं। जैसे रोजपरा की घटनाएं, सफलताएं, असफलताएं, रिश्ते और समय के साथ बदलते हालात। मगर जीवन का एक और आयाम भी है, जो दृश्य नहीं है, फिर भी उतना ही वास्तविक है। यह आयाम है कंपन, स्पंदन, वेब सूक्ष्म ऊर्जा, जो हमारे भीतर और चारों ओर निरंतर बहती रहती है। हम उसे देख नहीं पाते, फिर भी हम उसे महसूस अवश्य करते हैं। जैसे रंगों का प्रभाव केवल उनकी आकृति या चमक में नहीं, बल्कि उनकी ऊर्जा में छिपा होता है, वैसे ही जीवन की गहराई भी उसकी अनदेखी तरंगों में बसती है।

जीवन में कंपन का अर्थ केवल भौतिक विज्ञान की किसी परिभाषा से नहीं है। यह एक ऐसा अनुभव है, जो भावनाओं, विचारों और चेतना के स्तर पर घटित होता है। हम कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के प्रसन्न हो जाते हैं, तो कभी भीतर एक अनजानी उदासी उतर आती है। ये भावनाएं केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं होतीं, बल्कि हमारे भीतर चल रहे स्पंदनों की अभिव्यक्ति होती हैं। यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि उनके भीतर के कंपन अलग होते हैं।

जीवन ‘घटनाओं’ का नहीं, ‘अनुभवों’ का नाम है। दरअसल, जीवन ‘घटनाओं’ का नहीं, बल्कि ‘अनुभवों’ का नाम है और ये अनुभव हमारे भीतर के स्पंदनों से निर्मित होते हैं। जब हम यह समझने लगते हैं, तो हमारी दृष्टि अपने आप ही बाहर से भीतर की ओर मुड़ने लगती है। हम यह प्रश्न पूछने लगते हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है हमारी भावनाओं का स्रोत क्या है! यह भी कि क्या हम अपने अनुभवों के साक्षी बन सकते हैं! और यहीं

(मनीषा मंजरी)

अक्सर हम जीवन को उन दृश्यों में बांध देते हैं, जो हमारी आंखों के सामने घटित होते हैं। जैसे रोजपरा की घटनाएं, सफलताएं, असफलताएं, रिश्ते और समय के साथ बदलते हालात। मगर जीवन का एक और आयाम भी है, जो दृश्य नहीं है, फिर भी उतना ही वास्तविक है। यह आयाम है कंपन, स्पंदन, वेब सूक्ष्म ऊर्जा, जो हमारे भीतर और चारों ओर निरंतर बहती रहती है। हम उसे देख नहीं पाते, फिर भी हम उसे महसूस अवश्य करते हैं। जैसे रंगों का प्रभाव केवल उनकी आकृति या चमक में नहीं, बल्कि उनकी ऊर्जा में छिपा होता है, वैसे ही जीवन की गहराई भी उसकी अनदेखी तरंगों में बसती है।

जीवन में कंपन का अर्थ केवल भौतिक विज्ञान की किसी परिभाषा से नहीं है। यह एक ऐसा अनुभव है, जो भावनाओं, विचारों और चेतना के स्तर पर घटित होता है। हम कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के प्रसन्न हो जाते हैं, तो कभी भीतर एक अनजानी उदासी उतर आती है। ये भावनाएं केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं होतीं, बल्कि हमारे भीतर चल रहे स्पंदनों की अभिव्यक्ति होती हैं। यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि उनके भीतर के कंपन अलग होते हैं।

जीवन ‘घटनाओं’ का नहीं, ‘अनुभवों’ का नाम है। दरअसल, जीवन ‘घटनाओं’ का नहीं, बल्कि ‘अनुभवों’ का नाम है और ये अनुभव हमारे भीतर के स्पंदनों से निर्मित होते हैं। जब हम यह समझने लगते हैं, तो हमारी दृष्टि अपने आप ही बाहर से भीतर की ओर मुड़ने लगती है। हम यह प्रश्न पूछने लगते हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है हमारी भावनाओं का स्रोत क्या है! यह भी कि क्या हम अपने अनुभवों के साक्षी बन सकते हैं! और यहीं

से आत्मबोध की यात्रा प्रारंभ होती है।

इस यात्रा में सबसे बड़ी बाधा है, हमारी आदत, जो हर अनुभव को तुरंत नाम देने को आतुर होती है। हम हर भावना को ‘अच्छा’ या ‘बुरा’ कहकर सीमित कर देते हैं, लेकिन हम अगर इन स्पंदनों को बिना किसी निर्णय के देखें, तो वे



केवल ऊर्जा के रूप में प्रकट होते हैं। एक शुद्ध, गतिशील ऊर्जा, जो आती है और चली जाती है। इस दृष्टि से, जीवन एक स्थिर वस्तु नहीं, बल्कि एक सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है।

यह एक प्रवाह है, जिसमें हर क्षण कुछ नया जन्म लेता है और कुछ पुराना विलीन हो जाता है। और इसी प्रवाह में, हम अक्सर स्वयं को भूल जाते हैं, क्योंकि हम उन तरंगों से जुड़ जाते हैं, जो अस्थायी हैं। अगर हम इस भूल को पहचान लें, तो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है। हम यह समझने लगते हैं कि हमें हर भावना के साथ बहना नहीं है, बल्कि उसे देखना-समझना और उसके पार जाना है। इसी अवस्था में ‘जीवन’ एक अनुभव से उठकर एक ‘साधना

और कला’ बन जाता है।

इस संदर्भ में ‘कलाकार’ का रूपक अत्यंत सार्थक है। एक कलाकार जब अपने कैनवास पर रंग भरता है, तो वह केवल बाहरी चित्र नहीं बनाता, बल्कि अपनी आंतरिक स्थिति को व्यक्त करता है। उसके रंग उसके भीतर के स्पंदनों का रूप होते हैं। ठीक उसी प्रकार,

हमारा जीवन भी एक कैनवास है और हमारे विचार, भावनाएं और कर्म उसके रंग हैं। मगर यहां हम केवल कलाकार ही नहीं, बल्कि स्वयं के कैनवास भी हैं। यानी हम ही सृजनकर्ता हैं और हम ही सृजन। यह द्वैत और अद्वैत के बीच का वह सूक्ष्म बिंदु है, जहां जीवन अपनी सबसे गहन अनुभूति में प्रवेश करता है।

जब हम अपने विचारों को सजगता से देखने लगते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हर विचार एक बीज है, जो भविष्य के अनुभवों को जन्म देता है। हर भावना एक तरंग है, जो हमारे भीतर और बाहर दोनों को प्रभावित करती है। और हर कर्म उस तरंग को एक दिशा देता है।

‘जीवन का संगीत’ एक अत्यंत सूक्ष्म और सुंदर रूपक है

इस प्रकार, हम अनजाने में ही अपने जीवन का संगीत रचते रहते हैं। ‘जीवन का संगीत’ एक अत्यंत सूक्ष्म और सुंदर रूपक है। संगीत में स्वर होते हैं, लय होती है और एक संतुलन होता है। अगर कोई स्वर असंतुलित हो जाए, तो पूरी रचना प्रभावित हो जाती है। इसी प्रकार, हमारे जीवन में भी संतुलन आवश्यक है। यह संतुलन बाहरी परिस्थितियों से

नहीं, भीतर की सजगता से आता है। जब हमारे विचार, भावनाएं और कर्म एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं, तो जीवन में एक स्वाभाविक लय उत्पन्न होती है। जब यह लय स्थापित हो जाती है, तो जीवन में एक सहज सुंदरता प्रकट होती है, एक ऐसी सुंदरता, जो किसी प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि एक आंतरिक सामंजस्य का प्रतिबिंब होती है। हमारा जीवन में असंतुलन भी अति महत्वपूर्ण है। जैसे संगीत में आरोह-अवरोह, विराम और तीव्रता उसे पूर्ण बनाते हैं, वैसे ही जीवन के उतार-चढ़ाव भी उसे गहिराई देते हैं। दुख, संघर्ष और अनिश्चितता-ये सब भी उसी संगीत का हिस्सा हैं। इनसे बचने की नहीं, इन्हें समझने की आवश्यकता है। जब हम जीवन को इस दृष्टि से देखना प्रारंभ करते हैं, तो धीरे-धीरे हमारे भीतर एक नई संवेदनशीलता जन्म लेती है। हम अपने अनुभवों को केवल ‘जीने’ के बजाय ‘महसूस’ करने लगते हैं। हम हर क्षण में उपस्थित होने लगते हैं।

यही उपस्थिति हमें उस अदृश्य स्पंदन के और करीब ले जाती है, जो जीवन का मूल है। जीवन कोई बाहरी यात्रा नहीं है, जिसे हमें तय करना है। यह एक आंतरिक प्रक्रिया है, जिसे हमें अनुभव करना है। हम जितना अपने भीतर के स्पंदनों को समझते हैं, उतना ही जीवन स्पष्ट होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है, जब हम यह अनुभव करते हैं कि जीवन को समझने की आवश्यकता ही नहीं है, उसे केवल महसूस करने की आवश्यकता है। जीवन कोई समस्या नहीं, जिसे हल किया जाए, यह एक संगीत है, जिसे सुना जाए, जिया जाए और पूरी सजगता के साथ रचा जाए। जब हम इस संगीत को सच में सुन लेते हैं, तब हमें यह एहसास होता है, कि हम केवल श्रोता नहीं, बल्कि स्वयं उस अनंत रचना का एक जीवंत स्वर हैं।

संक्षिप्त समाचार

अमेरिका में भारतीय नागरिक गिरफ्तार: बेसबॉल बैट से हमला करने का आरोप

न्यूयॉर्क, एंजेसी। अमेरिका में अवैध रूप से दाखिल हुए एक भारतीय नागरिक को कथित



तौर पर बेसबॉल बैट से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।धवल अमरतभाई पटेल को सबसे पहले 16 मई को मैसाचुसेट्स के वॉर्सेस्टर पुलिस विभाग ने गिरफ्तार किया था। उस पर खतरनाक हथियार से हमला और मारपीट करने का आरोप लगाया गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, जिस शराब की दुकान में पटेल काम करता था वहां एक थाहक के साथ उसकी बहस हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद उसने बेसबॉल बैट उठाकर उस व्यक्ति पर हमला कर दिया। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि मैसाचुसेट्स के सैक्वअरी पॉलिटिशियंस ने आईसीई अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं किया और पटेल को बिना सूचना दिए जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद ने 18 मई को पटेल को गिरफ्तार कर लिया। मुताबिक, पटेल ने अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश किया था। कार्यवाहक सहायक सचिव लॉरेन बिस ने कहा कि भारत से आया यह अवैध व्यक्ति सोचता था कि वह बेसबॉल बैट से लोगों पर हमला कर सकता है। सैक्वअरी नेताओं ने उसे गिरफ्तार होने के बाद भी रिहा कर दिया।

भारत में एआई-दुर्लभ खनिज क्षेत्र में निवेश और सहयोग करेगा कनाडा

टोरंटो, एंजेसी। एआई, दुर्लभ खनिज समेत कई क्षेत्रों में सहयोग-निवेश के लिए कनाडाई कंपनियां भारत में दस्तक देंगी। कनाडा इस वर्ष



नवंबर में टीम कनाडा ट्रेड मिशन भारत भेजेगा। यह एलायन कनाडाई व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने केद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ किया। गोयल स्वच्छ ऊर्जा व एआई क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी के लिए कनाडाई निवेशकों के साथ बैठक की। उन्होंने कनाडा के कोर्पोरेट प्रमुखों संग द्विपक्षीय कार्ययोजना भी तैयार की। केद्रीय मंत्री ने मैक्केन फूड्स के अध्यक्ष मैक्स कोयुने, फेयरफेक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमि, के अध्यक्ष-सीईओ प्रेम वात्सा, समेत विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिले। इस दौरान उन्होंने वित्तीय सेवाओं, अवसरंचना, सतत कृषि, बैक-बीमा और दुर्लभ खनिज प्रसंस्करण में निवेश के लिए आमंत्रित किया। कनाडाई मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा, भारत में प्रस्तावित मिशन का लक्ष्य कनाडा की कंपनियों को भारत ले जाकर एआई, दुर्लभ खनिज, परमाणु व नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, डिजिटल अवसंरचना तथा उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसर तलाशना है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टोरंटो में कनाडा-इंडिया बिल्डिंग ब्रिजस कार्यक्रम में गोयल ने मुख्य भाषण दिया। इसमें उन्नत विनिर्माण, औषधि एवं जैव-प्रौद्योगिकी, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा तथा तेल-गैस से जुड़े 150 से अधिक व्यवसायिक प्रतिनिधियों, निवेशक समूहों और उद्योग संगठनों ने भाग लिया। ब्रैम्पटन के पियर्सन कन्वेंशन सेंटर में पीयूष गोयल ने भारत-कनाडा व्यापार गलियारे को मजबूत करने पर चर्चा की। आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण पर फोकस: कंपनी मुख्यों के साथ मुलाकात के दौरान, केद्रीय मंत्री ने भारतीय बाजार में कनाडाई कंपनियों के दीर्घकालिक संचालन का मूल्यांकन किया और उभरते औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में गहन भागीदारी को आमंत्रित किया।

बांग्लादेश में अधिकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप भैंसे की कुर्बानी रुकवाई, बताया क्यों बदला फैसला

ढाका, एंजेसी। बांग्लादेश में बकरीद से पहले एक अनोखे भैंसे ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। डोनाल्ड ट्रंप नाम का यह दुर्लभ भैंसा अपनी सुनहरी लहराती बालों और अलग दिखने वाली शकल के कारण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। अब सरकार ने इसकी कुर्बानी रुकवा दी है और इसे राष्ट्रीय चिड़ियाघर में रखने का फैसला किया है। यह मामला ढाका के बाहरी इलाके केरानीगंज का है। यह भैंसा एल्फोनो नाम की दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति से पीड़ित है। इस स्थिति में शरीर में मेलैनिन नाम का रंगद्रव्य बहुत कम बनता है, जिससे जानवर का रंग बेहद हल्का या सफेद दिखाई देता है। इसके सुनहरे बाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मशहूर हेयरस्टाइल जैसे लगते थे, इसलिए इसका नाम डोनाल्ड ट्रंप रखा गया। करीब 700 किलोग्राम वजन वाले इस भैंसे को बकरीद पर कुर्बानी के लिए खरीदा गया था। इसके नए मालिक मोनिरुज जमान ने बताया कि कुर्बानी से कुछ घंटे पहले पुलिस और सरकारी अधिकारी उनके घर पहुंचे और कहा कि सरकार ने इस दुर्लभ भैंसे को संरक्षण के लिए अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है। म्मोनिरुज जमान के अनुसार, उन्होंने किसी विवाद से बचने के लिए भैंसा अधिकारियों को सौंप दिया। अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि बदले में उन्हें मुआवजा या दूसरा जानवर दिया जाएगा। स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पशुधन विभाग का मानना ​​है कि यह भैंसा अभी काफी कम उम्र का है और इसे कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है।



मोनिरुज जमान ने बताया कि कुर्बानी से कुछ घंटे पहले पुलिस और सरकारी अधिकारी उनके घर पहुंचे और कहा कि सरकार ने इस दुर्लभ भैंसे को संरक्षण के लिए अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है। म्मोनिरुज जमान के अनुसार, उन्होंने किसी विवाद से बचने के लिए भैंसा अधिकारियों को सौंप दिया। अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि बदले में उन्हें मुआवजा या दूसरा जानवर दिया जाएगा। स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पशुधन विभाग का मानना ​​है कि यह भैंसा अभी काफी कम उम्र का है और इसे कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है।

देश-विदेश

पहचान छिपाई, बंदूकें रखीं... 30 सालों से पुलिस को चकमा दे रही जर्मनी की मोस्ट वांटेड महिला को 13 साल की सजा

बर्लिन, एंजेसी। करीब 30 वर्षों तक कानून की आंखों में धूल झोंककर छद्म नाम से सामान्य जीवन जीने वाली जर्मनी की मोस्ट वांटेड महिला डेनिएला क्लेटे को आखिरकार सजा मिल गई है। कोर्ट ने इसे कई सशस्त्र डकैतियों और जबरन वसूली के मामलों में 13 साल की जेल की सजा सुनाई है।

दरअसल, करीब तीन दशकों तक पुलिस को चकमा देकर बर्लिन में क्लाउडिया इवोन नाम की झूठी पहचान के साथ बेहद सामान्य दोहरी जिंदगी जी रही क्लेटे को डकैती, जबरन वसूली और अवैध हथियार रखने का दोषी पाया गया। पाए जाने के बाद 13 साल जेल की सजा सुनाई गई है। 67 वर्षीय डेनिएला क्लेटे को लगभग 30 वर्षों तक पुलिस से बचने के बाद फरवरी 2024 में बर्लिन में गिरफ्तार किया गया था।बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, कभी यूरोप की सबसे कुख्यात महिलाओं में से एक मानी जाने वाली वह बर्लिन में क्लाउडिया इवोन के छद्म



जीवन व्यतीत किया। 14 महीने तक चले इस हाई-प्रोफाइल मुकदमे का फैसला लोअर सैक्सोनी की वडेंन क्षेत्रीय अदालत ने सुना। डेनिएला क्लेटे को 1999 से 2016 के बीच किए गए अपराधों से संबंधित गंभीर डकैती, जबरन वसूली, फिरोती के लिए अपहरण और हथियार संबंधी उल्लंघन के छह मामलों में दोषी ठहराया गया। डेनिएला यूरोपोल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में खतरनाक घोषित की गई एकमात्र महिला क्लेटे थी। 30 से अधिक वर्षों तक, उसने बर्लिन के

करूजबर्ग जिले में क्लाउडिया इवोन की झूठी पहचान के तहत एक आश्चर्यजनक रूप से सामान्य दोहरा जीवन जिया। वह अपने कुत्ते को टहलाती थी, स्थानीय बच्चों को गणित पढ़ाती थी और अक्सर एक अफीकी-बाजीलियाई कैपोइरा नृत्य स्टूडियो जाती थी। अभियोजकों ने कहा कि क्लेटे ने अपने साथी पूर्व आरएएफ सदस्यों बुरखाई गारवेग और अर्नस्ट-वोल्कर स्टॉब के साथ मिलकर डकैतियां कीं, इसके साथी अभी भी फरार हैं। आरोप है कि तीनों ने सुनियोजित डकैतियों की एक श्रृंखला के माध्यम से लगभग 24 लाख यूरो चुराए, जिनका इस्तेमाल उन्होंने 1998 में आरएएफ के आधिकारिक रूप से भंग होने के बाद भूमिगत जीवन यापन के लिए किया। जज लार्स एंगेलके ने कहा कि यह गिरोह बेहद संगठित तरीके से काम करता था, फर्जी पहचान और किराए के वाहनों का इस्तेमाल करके भाग जाता था और लूटपाट को अपनी

गाजा में इस्राइल का बड़ा हमला हमास के दो बड़े कमांडर ढेर; नए सैन्य प्रमुख को भी मार गिराने का दावा

गाजा पट्टी, एंजेसी। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच इस्राइल ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान चलाते हुए दो वरिष्ठ आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। इस्राइली सेना ने कहा कि उत्तरी गाजा में किए गए हवाई हमलों में हमास के बड़े ऑपरेटिव निशाने पर थे। वहीं दूसरी ओर गाजा में आम नागरिकों के हताहत होने की खबरों ने एक बार फिर पूरे इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। लगातार हो रहे हमलों और जवाबी कार्रवाई के बीच युद्ध और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है।

इस्राइली रक्षा बल यानी आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने गाजा में हमास की सैन्य शाखा के नए प्रमुख मोहम्मद ओदेह को मार गिराया है। इस्राइल के अनुसार ओदेह सात अक्टूबर 2023 के हमले की साजिश रचने वालों में शामिल था। इस्राइल का कहना है कि वह हमास के खुफिया नेटवर्क का प्रमुख भी रह चुका था और हाल ही में उसे संगठन की सैन्य कमान सौंपी गई थी। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहु ने भी हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि सात अक्टूबर के हमले में शामिल हर व्यक्ति को खत्म किया जाएगा। इस कार्रवाई को



प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री इस्राइल काट्ज के निर्देश पर अंजाम दिया गया। जहां इस्राइल हमास पर बड़े हमलों का दावा कर रहा है, वहीं गाजा में आम लोगों की मौतों की खबरों भी लगातार सामने आ रही हैं। फलस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसायटी के मुताबिक, मध्य गाजा शहर में एक

रिहायशी मकान पर हुए हवाई हमले में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य घायल हुए हैं। गाजा के कई इलाकों में लगातार बमबारी के कारण लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचने में भारी परेशानी हो रही है। अस्पतालों पर दबाव बढ़ता जा रहा है और राहत सामग्री की कमी भी गंभीर चिंता बन चुकी है।

आईडीएफ ने यह भी दावा किया है कि उसने पूरे दिन लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले किए। इस्राइल के अनुसार हिजबुल्लाह के सैन्य ढांचे, कमांड सेंटर और लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया गया। सेना ने कहा कि सिर्फ इस ससाह के दौरान हिजबुल्लाह के 550 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। लेबनान सीमा पर लगातार बढ़ रही सैन्य गतिविधियों ने पूरे पश्चिम एशिया में नए संघर्ष का खतरा और बढ़ा दिया है। हिजबुल्लाह भी लगातार इस्राइल पर जवाबी हमले करने का दावा कर रहा है।

कनाडा में तिरंगे का अपमान: खालिस्तानियों ने भारतीय उच्चायुक्त का काफिला रोका, तमाशबीन बनी रही पुलिस

ओटावा, एंजेसी। कनाडा की धरती पर एक बार फिर भारत विरोधी गतिविधियों ने शर्मनाक रूप ले लिया। वैंकूवर में भारतीय उच्चायुक्त दिनेश पटनायक के काफिले को खालिस्तान समर्थकों ने घेर लिया और खुलेआम भारतीय तिरंगे का अपमान किया गया। प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़ा कट्टरपंथी इंदरजीत सिंह गोसल सुरक्षा घेरा तोड़कर सीधे उच्चायुक्त की गाड़ियों के सामने पहुंच गया। उसने भारतीय ध्वज को फाड़ने और पैरों तले रौंदने की कोशिश की। आसपास मौजूद भीड़ भारत विरोधी नारे लगाती रही, जबकि कनाडाई सुरक्षा व्यवस्था तमाशबीन बनी दिखाई दी। घटना उस समय हुई जब भारतीय उच्चायुक्त एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। खालिस्तानी समर्थक पहले से वहां जमा थे और जैसे ही काफिला पहुंचा, माहौल को उग्र बना दिया गया। पुलिसकर्मी बाद में दौड़ते हुए पहुंचे, लेकिन तब तक तिरंगे का अपमान पूरी दुनिया देख चुकी थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि गोसल ने अपने इस कृत्य को सही ठहराने की कोशिश करते हुए भारतीय उच्चायुक्त पर ही जान से मारने की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। बिना किसी प्रमाण के लगाए गए इन आरोपों को लेकर खालिस्तानी समर्थक लगातार जहर उगलते रहे। यह ही इंदरजीत सिंह गोसल है जिसे खालिस्तानी चरमपंथी गुरुपतवंत सिंह पन्नू का बेहद करीबी माना जाता है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में उसका नाम लगातार सामने आता रहा है। हिंदू मंदिरों के बाहर हिंसा, धमकी और उग्र प्रदर्शनों में भी उसका नाम जुड़ चुका है। भारत लंबे समय से कनाडा को चेतावनी देता रहा है कि वहां चरमपंथी तत्वों को खुली छूट मिल रही है। मगर हर बार अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर भारत विरोधी ताकतों को संरक्षण मिलता दिखाई देता है। भारतीय समुदाय में इस घटना को लेकर भारी रोष है। कनाडा निवासी जोगिंदर सिंह का कहना है कि तिरंगे का अपमान केवल एक झंडे का अपमान नहीं, बल्कि पूरे भारत और करोड़ों भारतीयों की भावनाओं पर हमला है।



भारत को पाकिस्तान और चीन से ही सबसे बड़ा खतरा, रिपोर्ट में बड़ा दावा

सिंगापुर, एंजेसी। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत की पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां आगे भी पाकिस्तान और चीन के इर्द-गिर्द केंद्रित रहेंगी। सिंगापुर में सप्ताहांत में अंतरराष्ट्रीय रक्षा संवाद आयोजित होने जा रहा है, उससे पहले एक रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें यह दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भविष्य में किसी भी संभावित पारंपरिक युद्ध की प्रकृति स्थानीय ही रहेगी। लंदन स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटैजिक स्टडीज की ‘एशिया-पैसिफिक रीजनल सिक्वोरिटी असेसमेंट’ नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपने दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसी देशों के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवादों के कारण बड़े भ्रमाने पर पारंपरिक सैन्य अभियानों के लिए सेना को तैयार कर रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, चीन के साथ भारत के सीमा विवाद अपेक्षाकृत पारंपरिक प्रकृति के हैं और इनके भारत-पाक संघर्षों जैसी तीव्रता तक पहुंचने की संभावना कम है। इसके बावजूद भारत की चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ सीमाएं सैन्य रूप से संवेदनशील बनी रहेंगी। हिंद महासागर क्षेत्र से बाहर भारत की व्यापक एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सक्रिय सैन्य भूमिका निभाने की संभावना कम है। साथ ही भारत,

ताइवान को लेकर संभावित अमेरिका-चीन संघर्ष से भी दूरी बनाए रखने की कोशिश करेगा।



नयुद्ध, न शांति वाली स्थिति बनी रहेगी

रिपोर्ट में भारत की स्थिति को ‘न युद्ध, न शांति’ वाली हाइब्रिड चुनौती बताया गया है, जिसमें चीन और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान और चीन के खिलाफ अभियानों से मिले अनुभवों के आधार पर भारतीय सैन्य सिद्धांत लगातार विकसित हो रहे हैं और

मित्रा ई.ओ.आर.एस शुरू ,6 मिलियनट्रेंड-फर्स्ट फैशन, ब्यूटी और लाईफ स्टाईल प्रोडक्ट मिलेंगे अब तक के सबसे आकर्षक मूल्य में

मित्रा ने भारत के ई-लाईफस्टाईल ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आज अपनी एंड ऑफरीजन सेल (ई.ओ.आर.एस) के 24वें एडिशन की घोषणा कीई.ओ.आर.एस के इस एडिशन में 6 मिलियन से अधिक स्टाईल मिलेंगे, जो भारत में फैशन और लाईफस्टाईल ईकोसिस्टम के विकास में मित्रा की महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूत करेंगे। इसमें जहाँ उभरते हुए ब्रांड्स को विस्तार करने का अवसर मिलेगा, वहीं देश के करोड़ों ग्राहकों को आकर्षक मूल्य में ट्रेंड-फर्स्ट सेलेक्शन और सुविधा प्राप्त होगी। ई.ओ.आर.एस में उभरते हुए ब्रांड्स को बढ़ावा मिलता रहेगा इस बार ई.ओ.आर.एस में हिस्सा लेने वाले हजारों ब्रांड्स में ग्लोबल, डोमेस्टिक और होमग्रोन डी2सी ब्रांड शामिल हैं।साथ ही, 15,000 उभरते हुए ब्रांड, जिनमें ई.ओ.आर.एस में पहली बार हिस्सा ले रहे 5,000 ब्रांड शामिल हैं, मित्राप्लेटफॉर्म की टेक्नोलॉजी, क्रिएटर ईकोसिस्टम और पूरे देश में पहुँच की मदद से भारत के करोड़ों ग्राहकों तक पहुँचेंगे। ई.ओ.आर.एस उनके विकास में मुख्य भूमिका निभाता रहेगा और उभरते हुए ब्रांड्स को ज्यादा विजिबिलिटी, नए सेलेक्शनलॉन्च और कैटेगरी विस्तार के माध्यम से ज्यादा मांग आकर्षित करने में मदद करेगा। ये ब्रांड एपरेल, फुटवियर, एक्सेसरीज़आदि में लगभग 13 लाख स्टाईल पेश करेंगे। इन ब्रांड्स को मित्रा की आधुनिक टेक्नोलॉजी द्वारा सर्च एवं शॉपिंग इनसाइट्समिलेंगी। जिससे वो ट्रेंड्स और डिमांड पैटर्न को समझ पाएंगे। उन्हें सिंप्लोफ़ईड परफॉर्मेंस डैशबोर्ड मिलेगा। साथ ही, एक समर्पित पार्टनर सपोर्ट टीम ब्रांड्स को मित्रा पर अपना ई-कॉमर्स व्यवसाय आगे बढ़ाने में मदद करेगी।

बांग्लादेश में गहरा संकट: शेख हसीना ने ईद पर हिंसा, अर्थव्यवस्था और कानून-व्यवस्था पर चिंता जताई

ढाका, एंजेसी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ईद-उल-अजहा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह त्योहार ऐसे समय आया है जब देश गहर संकट और कठिनाई का सामना कर रहा है। हसीना ने बांग्लादेश के लोगों के दर्द और पीड़ा पर गंभीर चिंता व्यक्त की। अवामी लीग द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए एक बयान में हसीना ने ये बातें कहीं। उन्होंने बताया कि पिछले 21 महीनों से अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को क्रूर हत्याओं, लगातार हमलों और झूठे मामलों का सामना करना पड़ा है। कई पाटी सदस्य अभी भी जेल में बंद हैं। उन्होंने आगे कहा, केवल हमारा राजनीतिक परिवार ही नहीं, बल्कि देश के लोग भी भारी पीड़ा सह रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री ने खसरा से सेकड़ों बच्चों की असामयिक मृत्यु, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा और बलात्कार का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था का पतन और तबाह हुई अर्थव्यवस्था ने देश को गहरे अंधकार की ओर धकेल दिया है। पिछले सप्ताह अवामी लीग ने अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों पर हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। पार्टी ने चेतावनी दी कि इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की लगातार चुपी देश को और अधिक क्रूरता और लंबे समय तक राजनीतिक हिंसा की ओर धकेल सकती है। अवामी लीग के अनुसार, जमीनी स्थिति बताती है कि पार्टी से जुड़ा कोई भी व्यक्ति अब सुरक्षित नहीं है, भले ही उसने कोई गलत काम न किया हो। इस महीने की शुरुआत में पार्टी ने कहा था कि बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा में चिंताजनक बढ़ोतरी हो रही है। अवामी लीग ने कहा कि देश भर में महिलाएं और बच्चे लगातार डर और असुरक्षा में जी रहे हैं।



महिलाओं पर मानसिक बोझ बढ़ रहा, अदृश्य दबाव पर अध्ययन में बड़ा खुलासा

रूप से थका देता है। अध्ययन में यह भी सामने आया कि महिलाएं खुद के लिए समय निकालने



में भी अपराधबोध महसूस करती हैं। प्रोफेसर रूपैनर ने बताया कि कई महिलाएं अपनी जरूरतों से ज्यादा परिवार की जरूरतों को प्राथमिकता देती हैं। शोध के दौरान कुछ महिलाओं को आर्थिक सहायता दी गई, लेकिन अधिकांश महिलाएं वह पैसा खुद पर खर्च करने से हिचक रही थीं। वे उसे परिवार के लिए इस्तेमाल करना चाहती थीं। हालांकि जब महिलाओं ने खुद पर समय और संसाधन खर्च किए तो उनके मानसिक तनाव में कमी देखी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाओं को आत्म-देखभाल और जरूरत पड़ने पर बाहरी मदद लेने को लेकर अपराधबोध छोड़ना होगा। अध्ययन में महिलाओं के मानसिक बोझ को आठ हिस्सों में बांटा गया है। इसमें घर की योजना बनाना, परिवार की भावनात्मक देखभाल करना,

रिशतों को संभालना और त्योहारों या खास मौकों को यादगार बनाने की जिम्मेदारी शामिल है। इसके अलावा परिवार के सपनों को पूरा करने की चिंता, खुद को फिट रखने का दबाव और परिवार की सुख्खा को लेकर लगातार सोच भी महिलाओं पर असर डालती है। सबसे बड़ा दबाव यह होता है कि महिलाएं हमेशा यह सोचती रहती हैं कि वे परिवार और समाज के लिए पर्याप्त कर पा रही हैं या नहीं। यही लगातार चलने वाली मानसिक प्रक्रिया उन्हें भावनात्मक रूप से थका देती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि जब महिलाओं को शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और फैसले लेने का अधिकार मिलता है, तब घरों में जिम्मेदारियों का बंटवारा बेहतर होता है। इससे रिश्ते भी मजबूत होते हैं और महिलाओं का मानसिक तनाव कम होता है। अध्ययन में यह भी कहा गया कि परिवारों को अब घर के अदृश्य मानसिक श्रम को समझना होगा। केवल खाना बनाना या सफाई करना ही काम नहीं है, बल्कि परिवार की हर छोटी-बड़ी चिंता को लगातार संभालना भी बड़ा मानसिक श्रम है। अगर घरों में जिम्मेदारियां बराबर बांटी जाएं तो महिलाओं की मानसिक स्थिति बेहतर हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि आधुनिक जीवनशैली में महिलाओं पर दोहरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। वे बाहर नौकरी भी कर रही हैं और घर की मानसिक जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं। यही कारण है कि तनाव, चिंता और मानसिक थकावट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

इंडियन स्टार्टअप इंडस्ट्री के पोस्टर बॉय बायजू रवींद्रन बने हीरो से जीरो

नई दिल्ली, एजेंसी
कभी देश की सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप रही बायजू के फाउंडर बायजू रवींद्रन को सिंगापुर की एक अदालत ने 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। उन्हें कोर्ट की अवमानना का दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई गई है और सजा के लिए 15 जून को पेश होने को कहा गया है। बायजू रवींद्रन को कभी भारतीय स्टार्टअप की सबसे सटोरी का पोस्टर बॉय माना जाता था। इस एडटेक स्टार्टअप की वैल्यू 2022 में 22 अरब डॉलर पहुंच गई थी और उसने वैश्विक निवेशकों से 4 अरब डॉलर से अधिक जुटाए थे। दुनियाभर के निवेशकों ने इसमें पैसा लगाया था और आज वे अपना पैसा पाने के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं।



कंपनी का घाटा
लेकिन कोरोना महामारी के बाद जैसे ही डिमांड सामान्य हुई, बायजू के रेवेन्डू की रफ्तार मंद हो गई जबकि ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ गया। बायजू ने पूरी दुनिया में करीब 3 अरब डॉलर की खरीदारी की। इसके लिए कंपनी ने कर्ज लिया। इसमें से 1.2 अरब डॉलर का कर्ज विदेशी निवेशकों से लिया गया। अधिग्रहण से कंपनी ने दुनियाभर में अपने पैर पसारें लेकिन इससे कॉस्ट बहुत बढ़ गई। फाइनेंशियल ईयर 2022 में ही कंपनी का घाटा 8,245 करोड़ रुपये था जो 2021 की तुलना में करीब दोगुना था। इसके बाद निवेशकों ने कंपनी के कामकाज पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। ऑडिटर्स ने भी कंपनी के भविष्य को लेकर चिंता जताई। नतीजा यह हुआ कि कंपनी की वैल्यू 22 अरब डॉलर से गिरकर 8 अरब डॉलर रह गई और फिर यह 1 अरब डॉलर तक गिर गई। कंपनी को खुद को बचाए रखने के लिए राइट्स इश्यू और एसेट सेल्स का सहारा लेना पड़ा। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में ऑडिटेड रिजल्ट फाइल करने में 17 महीने लगा दिए।

हीरो से जीरो
कंपनी के ऑडिटर डेलॉयट ने रिजाइन कर दिया और कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी कंपनी को नोटिस थमा दिया। इससे कंपनी की इमेज को बड़ा लगा। निवेशकों के कान खड़े हो गए और अपना पैसा पाने के लिए वे कानूनी रास्ते तलाशने लगे। कंपनी ने अमेरिका की एक अदालत में लेंडर्स को घसीट लिया जबकि क्रेडिटर्स ने कंपनी पर 533 मिलियन डॉलर के गबन का आरोप लगाया। इसके बाद कंपनी एक के बाद एक कई विवादों में फंसी चली गई। आज हालत यह है कि बायजू अपना वजुद बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। बड़े निवेशक निकल चुके हैं और कंपनी खुद को इनसॉल्वेंसी प्रॉसीडिंग से बचाने की जद्दोजहद में लगी है। अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में बायजू के खिलाफ केस चल रहे हैं। कंपनी के फाउंडर बायजू रवींद्रन की नेटवर्थ भी अप्रैल 2023 की शुरुआत में 2.1 अरब डॉलर थी लेकिन आज उनकी नेटवर्थ जीरो है।

दो महीने के लो पर फिसला सोना

नई दिल्ली। सोने की कीमत आज इंटरनेशनल मार्केट में दो महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। अमेरिका ने ईरान पर फिर हमला किया है। इससे डॉलर की कीमत में तेजी आई है। साथ ही कच्चे तेल की कीमत में भी करीब 4 फीसदी उछाल आई है और महंगाई को लेकर एक बार फिर निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। इससे इंटररेस्ट रेट आउटलुक को लेकर एक बार फिर अनिश्चितता का दौर शुरू हो चुका है। इस सबका असर सोने की कीमत पर देखने को मिल रहा है। स्पॉट गोल्ड 1.1 फीसदी गिरावट के साथ 4,406.81 प्रति ओंस पर आ गया।



भारत में कीमत
इस बीच भारत के सराफा बाजार में भी सोने और चांदी की कीमत में गिरावट दिख रही है। गुड रिटर्न्स के मुताबिक 24 कैरेट वाला सोना 2,230 रुपये की गिरावट के साथ 1,56,060 रुपये पर आ गई। 22 कैरेट वाले सोने की कीमत भी 2,050 रुपये की गिरावट के साथ 1,43,050 रुपये रह गई जबकि 18 कैरेट वाला सोना 1,680 रुपये की गिरावट के साथ 1,17,040 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। चांदी की कीमत भी 10,000 रुपये की गिरावट के साथ 2,75,000 रुपये प्रति किलो रह गई है।

सरकारी खजाने में पिछले साल रिलायंस ने जोड़े 2.16 लाख करोड़, सीएसआर खर्च भी बढ़ा



मुंबई। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से बड़ी खबर आई है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सरकारी खजाने में दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का योगदान किया है। इसमें टैक्स, ड्यूटी, लेवी और सरकार को किए गए अन्य भुगतान शामिल हैं।

एनुअल रिपोर्ट से हुआ खुलासा
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुरुवार को आलोच्य वर्ष के लिए एनुअल रिपोर्ट को जारी किया। इसके मुताबिक वर्ष 2025-26 के दौरान सरकारी खजाने में 2,16,472 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। एक साल पहले यानी वित्त वर्ष 2024-25 में यह योगदान 2,10,269 करोड़ रुपये था। इस तरह सालाना आधार पर इसमें करीब 2.95 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

15 लाख करोड़ से ज्यादा का योगदान

कंपनी का कहना है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज का राष्ट्रीय कोष में कुल योगदान 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। एफवाई26 में रिलायंस ने कुल 4,63,448 करोड़ रुपये की वैल्यू जोड़ी, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा सरकार को मिला। कंपनी द्वारा बनाई गई हर 100 रुपये की वैल्यू में से करीब 47 रुपये सरकारी खजाने में गए।

सीएसआर पर भी खर्च बढ़ा

इसी दौरान रिलायंस का समाजिक कार्यों पर भी खर्च बढ़ा है। एफवाई26 में कंपनी ने कॉर्पोरेट सोशल रिसपॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर के मद में 2,248 करोड़ रुपये खर्च किए, जो पिछले वित्त वर्ष के 2,156 करोड़ रुपये से 4.3 प्रतिशत अधिक है। कोविड के बाद से रिलायंस का कुल सीएसआर खर्च 9,500 करोड़ रुपये से ज्यादा का हो गया है।

ईवी इंडस्ट्री के कार्बन ब्लैक ने बदल दी भारत की किस्मत, रूस-चीन भी रह गए पीछे



नई दिल्ली। आमतौर पर निवेशक इलेक्ट्रिक वाहन सप्लाय चैन का नाम सुनते ही लिथियम, कोबाल्ट या सेमीकंडक्टर्स के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन इस रेस में एक ऐसा गुमनाम हीरो उभर कर सामने आ रहा है, जो चुपके से ईवी बैटरी, टायर्स, केबल्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का आधार बन चुका है। वह चीज है- कार्बन ब्लैक। चौकाने वाली बात यह है कि इस महत्वपूर्ण औद्योगिक सामग्री के प्रोडक्शन में भारत वैश्विक स्तर पर अपना दबदबा बना रहा है। दशकों से कार्बन ब्लैक को केवल एक साधारण कर्मांडी केमिकल माना जाता था, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से टायरों को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए किया जाता था। लेकिन ईवी क्रांति ने इस पारंपरिक उद्योग की परिभाषा बदल दी है। जब कार्बन ब्लैक को बेहद सटीक नियंत्रण और उच्च तकनीकों के साथ तैयार किया जाता है, तो यह स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक में बदल जाता है। यह उच्च मूल्य वाली सामग्री अब लिथियम-आयन बैटरी, कंडक्टिव प्लास्टिक्स और सेमीकंडक्टर्स जैसे एडवांस्ड क्षेत्रों में इस्तेमाल हो रही है।

तेजी से पैसा चीन से बाहर भेज रहे हैं लोग, एक साल में निकल गए 1 ट्रिलियन, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा

नई दिल्ली। अमेरिका के बाद चीन दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है। पूरी दुनिया के बाजार चीन से आने वाले सस्ते सामान से भरे पड़े हैं। चीन की गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक सामान और टेक्नोलॉजी दुनियाभर में छर रही है। लेकिन चीन एक बड़ी मुश्किल का सामना कर रहा है। देश से भारी मात्रा में पैसा बाहर भेजा जा रहा है। पिछले साल यानी 2025 में करीब 1 ट्रिलियन डॉलर की पूंजी विदेश भेजी गई जो अब तक का रिकॉर्ड है। देश में 2006 से इस तरह के आंकड़े रखने की शुरुआत हुई थी। पिछले पांच साल में यानी 2021 से देश से कैपिटल आउटफ्लो दोगुना हो चुका है। चीन के निवेशक विदेशी ब्रोकर्स के जरिए देश से पैसा निकाल कर विदेशी बाजारों में लगा रहे हैं। यह फंड खासकर हॉंग

कॉन्ग और अमेरिका के बाजारों में निवेश किया जा रहा है। चीन के इसे रोकने के लिए 22 मई को क्रॉस-बॉर्डर स्टॉक ट्रेडिंग पर पाबंदियां लगा दीं। चीन की सरकार ने सभी अवैध अकाउंट्स को दो साल में लिक्विडेट करने का ऑर्डर दिया है।

तीन कंपनियों पर फाइन

चीन ने साथ ही तीन ऑफशोर ऑनलाइन ब्रोकर्स पर फाइन भी लगाया है। इनमें हॉन्ग कॉन्ग की कंपनी फूटू, सिंगापुर की कंपनियां टाइगर ब्रोकर्स और लॉनाब्रिज सिन्योरिटीज शामिल हैं। इन कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने चीनी निवेशकों को 330 मिलियन डॉलर के विदेशी शेयर बेचे और इसके लिए सरकार से परमिशन नहीं ली। चीन की सरकार देश से बढ़ते कैपिटल आउटफ्लो को रोकने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।



ग्लोबल ऑटो मार्केट में क्रांति

दुनियाभर में बिकने वाली हर चौथी कार ईवी



मुंबई। दुनियाभर में इलेक्ट्रिक कारों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। अब इसका रिजल्ट भी सामने आता हुआ नजर आ रहा है। 2025 में बड़ी संख्या में लोगों ने इलेक्ट्रिक कारों को खरीदा है। इंटरनेशनल एनजी एजेंसी के लेटेस्ट ग्लोबल ईवी आउटलुक 2026 के मुताबिक, ग्लोबली इलेक्ट्रिक कारों की सेल 2025 में 20 फीसदी बढ़ी है। 2025 में इलेक्ट्रिक कारों की सेल 2 करोड़ के पार पहुंच गई है। दुनियाभर में 2025 में बिकने वाली सभी कारों में 25 फीसदी इलेक्ट्रिक हैं। इसका ये भी मतलब है कि ग्लोबली बिकने वाली हर चौथी कार इलेक्ट्रिक है। ये ग्लोबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी सफलता है। कुछ साल पहले तक लोग इलेक्ट्रिक कारों को चुनिंदा लोगों का साधन मान रहे थे। अब ये कारें मुख्य धारा का हिस्सा बन चुकी हैं और इनके वजुद को नकारा नहीं जा सकता है। हालांकि, इलेक्ट्रिक कारों का ये

ट्रेंजेक्शन हर मार्केट में एक जैसा नहीं है। कुछ मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों की मांग अच्छी खासी बढ़ी है, जबकि कुछ में इनका मार्केट अभी शुरुआती चरण में है। इंटरनेशनल एनजी एजेंसी के ग्लोबल ईवी आउटलुक 2026 में जिस 25 फीसदी डेटा की बात की गई है, उसमें बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल और प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल दोनों ही शामिल हैं। 2025 में हुई कुल इलेक्ट्रिक कारों की सेल में 65 फीसदी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं। यानी जिन्हें चार्ज करके यूज किया जाता है। इसके अलावा 35 फीसदी में रेंज एक्स्टेंडर और प्लग-इन हाइब्रिड दोनों शामिल हैं। 2025 में इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल में नॉर्वे सबसे ऊपर है। इस देश में बिकने वाली नई कारों में 97 फीसदी इलेक्ट्रिक हैं। इसके अलावा डेनमार्क, स्विडन, चीन और यूनाइटेड किंगडम ऐसे देश हैं, जहां आधी से ज्यादा बिकने वाली नई कारें इलेक्ट्रिक हैं। इन देशों में इलेक्ट्रिक कारों की सेल क्रमशः 71 फीसदी, 61 फीसदी, 53 फीसदी और 55 फीसदी है। भारतीय बाजार की बात करें, तो यहां इलेक्ट्रिक वाहनों की सेल टू-व्हीलर और थ्री व्हीलर मार्केट में हुई है।

ओएनजीसी बनावत वेदांता: कैम्बे बेसिन ऑयल ब्लॉक पर कब्जे की जंग, दिल्ली हाईकोर्ट में अटका मामला



नई दिल्ली। गुजरात के कैम्बे बेसिन में एक अहम ऑयल एंड गैस ब्लॉक के कंट्रोल को लेकर सरकारी तेल कंपनी ओएनजीसी और प्राइवेट कंपनी वेदांता के बीच कानूनी खींचतान जारी है। सरकार ने इस ब्लॉक का कॉन्ट्रैक्ट वेदांता के लिए आगे बढ़ाने से मना कर दिया था और ओएनजीसी को इसकी कमान संभालने को कहा था। लेकिन वेदांता ने इस फैसले को लेकर सरकारी तेल कंपनी वेदांता के बीच कानूनी खींचतान जारी है। सरकार ने इस ब्लॉक का कॉन्ट्रैक्ट वेदांता के लिए आगे बढ़ाने से मना कर दिया था और ओएनजीसी को इसकी

विवाद की शुरुआत और सरकार का कड़ा फैसला

इस पूरे विवाद की जड़ में प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट (पीएससी) है, जो सरकार और तेल कंपनियों के बीच होता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 19 सितंबर 2025 को एक आदेश जारी करके इस ब्लॉक के कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने (एक्सटेंशन) से साफ इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि इस ब्लॉक में ओएनजीसी की 50 प्रतिशत, वेदांता की 40 प्रतिशत और इनवैनियर पेट्रोड्राइन लिमिटेड की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी है। सरकार के इस फैसले के बाद ओएनजीसी को तुरंत ब्लॉक का कामकाज अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया गया था। ओएनजीसी ने इस आदेश का पालन करते हुए 20 सितंबर 2025 को गुजरात के सुवाली में अपनी एक ऑपरेशनल टीम भी तैनात कर दी थी, लेकिन वेदांता ने उसे अब तक कामकाज नहीं सौंपा है।

आगे का आउटलुक

गौरतलब है कि कैम्बे ब्लॉक पर रोक लगाने से पहले, सरकार ने वेदांता के दो अन्य अहम ब्लॉक्स (राजस्थान और राववा फील्ड) का कॉन्ट्रैक्ट 10 साल के लिए बढ़ा दिया था। लेकिन इस बार एक्सटेंशन न मिलने के कारण नियमों के मुताबिक ब्लॉक को सरकार को लौटाना था। अब ओएनजीसी पूरी तरह से तैयार बैठी है कि सरकार के निर्देश मिलते ही वह ब्लॉक का कंट्रोल ले ले। फिलहाल, दोनों ही कंपनियों और ऊर्जा सेक्टर की निगाहें दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि इस अहम ऑयल ब्लॉक की वाबी भविष्य में किसके पास रहेगी।

कितना अहम है यह कैम्बे बेसिन ब्लॉक?

गुजरात के अपतटीय क्षेत्र में स्थित सीबी/2 ब्लॉक में लक्ष्मी और गौरी नाम के दो अहम फील्ड्स हैं। यहां से रोजाना लगभग 3,400 बैरल कच्चा तेल और 3.4 लाख स्टैंडर्ड व्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन होता है। इस ब्लॉक का मूल कॉन्ट्रैक्ट 30 अगस्त 1998 को साइन हुआ था और इसकी समय सीमा 30 जून 2023 को ही खत्म हो चुकी थी। हालांकि, रिन्यूअल की अर्जी पेंडिंग होने की वजह से वेदांता का कंसोर्टियम अब तक इसे चला रहा था। वेदांता के प्रवक्ता के अनुसार, यह ब्लॉक कंपनी की कुल कमाई में 0.3 प्रतिशत से भी कम का योगदान देता है।



ताइवान के ताइपे में एनवीडिया के नए मुख्यालय 'कॉन्स्टेलेशन' के निर्माण स्थल पर आयोजित कर्मचारी समारोह में कंपनी के सीईओ जेनसन हुआंग का विशेष सम्मान किया गया। ताइपे के मेयर वेन च्यांग ने उन्हें पारंपरिक चीनी कैलिग्राफी भेंट की, जिसमें एनवीडिया और 'हुआंग' नाम से जुड़े प्रतीकात्मक संदेश शामिल थे। कार्यक्रम में तकनीक, संस्कृति और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिला।

पेट्रोल-डीजल की कोई किल्लत नहीं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का दावा- मांग से ज्यादा है सप्लाई

नई दिल्ली, एजेंसी।

पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने बुधवार को कहा कि देश में घरेलू मांग पूरी करने के लिए पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त से अधिक आपूर्ति है और इन ईंधनों की कोई किल्लत नहीं है। इसके साथ ही उसने सैब्सिडी वाले खुदरा ईंधन को औद्योगिक उपयोग में लाए जाने पर चेतावनी भी दी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दुनिया के चौथे बड़े रिफाइनिंग केंद्र भारत में 22 रिफाइनरियों की कुल 25.81 करोड़ टन शोधन क्षमता है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश ने 24.32 करोड़ टन घरेलू खपत के मुकाबले पर्याप्त ईंधन का उत्पादन किया और 6.15 करोड़ टन पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात भी किया।



बयान के मुताबिक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों, राज्यों और उद्योग संघों के साथ लगातार संपर्क में हैं ताकि निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

मंत्रालय ने कहा कि राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और फिक्की एवं सीआईआई जैसे उद्योग मंडलों के साथ समीक्षा में पेट्रोलियम उत्पादों की जमीन पर कोई किल्लत नहीं पाई गई। मंत्रालय ने कहा कि जहां कहीं आपूर्ति में कमी नजर आ रही है, वह आपूर्ति की समस्या न होकर कीमत के अंतर का फायदा उठाने का नतीजा है। सरकार ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी पर रोजाना करीब 550 करोड़ रुपये का नुकसान उठाकर उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचा रही हैं। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि यह लाभ खुदरा उपभोक्ताओं के लिए है, लेकिन कुछ औद्योगिक खरीदार सस्ती दरों का फायदा उठाने के लिए थोक के बजाय खुदरा बाजार से ईंधन खरीद कर रहे हैं। इससे स्थानीय स्तर पर दबाव बन रहा है। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से निजी ईंधन विक्रेताओं की डीजल बिक्री में करीब 38 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के माध्यम से थोक की कंपनियों के माध्यम से थोक कीमतों में लगभग 29 प्रतिशत कमी आई है। सरकार ने राज्यों से ईंधन की जमाखोरी, कालाबाजारी, अवैध भंडारण और हेराफेरी पर रोक लगाने के लिए विशेष प्रवर्तन दल बनाने को कहा है। साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों से बचें और आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

